लहना

बनाम

हरियाणा राज्य

22 जनवरी 2002

[एम.बी.शाह, बी.एन. अग्रवाल और अरिजीत पसायत, जे.जे.]

दण्ड संहिता 1860-

धारा 302-घायल चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई मौत की सजा-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर, दोषसिद्धि बरकरार-हालांकि अपराध करने की शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं है, हालांकि यह कार्य क्रूर था-धरातल पर अपनी आजीविका से वंचित होने पर आरोपी ने अपनी नाराजगी का प्रदर्शन किया-झगड़ों की आवृत्ति हत्या करने की भयावह योजना की कमी का संकेत देती है-इसलिए मौत की सजा उचित नहीं है-सजा को आजीवन कारावास में संशोधित किया गया।

धारा 324-घायल चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के तहत दोषसिद्धि -निर्धारित किया गया, विश्वसनीय है- इस बात को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

धारा 458-के तहत दोषसिद्धि-क्योंकि अपराध के घटकों के अस्तित्व

के बारे में निचली अदालतों द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए दोषसिद्धि को अपास्त किया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 354 (3), 360 और 361-हत्या के लिए दंड-निर्धारक कारक-अपराधी का व्यक्तित्व जैसा कि उसके चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898-धारा 367 (5)-दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 में सुधार के लिए अपराधी की व्यवहार्यता से प्रकट होता है।

आपराधिक विचारणः-संबंधित गवाह-संबंध की विश्वसनीयता किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।

अभियुक्त पर चोट-अभियोजन मामले पर प्रभाव-निर्धारित किया गया, जैसा कि स्वयं अभियोजन संस्करण को प्रभावित नहीं करता है-लेकिन जब चोटों और उनकी श्रृंखला की व्याख्या नहीं की जाती जब वे महत्वपूर्ण होते हैं।

सजाः- योग्य सजा का सिद्धांत-दण्ड की आनुपातिकता पर विचार किया गया-अत्यधिक सजा बिना अपराध के सजा है।

अपीलार्थी-अभियुक्त पर धारा 302, 458 और 324 आई. पी. सी. के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि पैतृक भूमि को लेकर आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के

बीच विवाद के कारण, उसने अपनी मां, भाई और साली की हत्या कर दी और अपने पिता (पीडब्लू 6) और भतीजे (पीडब्लू 7) को घायल कर दिया। विचारण के दौरान, सबूत यह था कि घटना से दो-तीन दिन पहले,गंभीर झगड़ा हुआ था और आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच जमीन को लेकर लगातार झगड़ा हुआ था और आरोपी के मृत भाई और पीडब्लू 6 के कई दुश्मन थे क्योंकि वे संदिग्ध थे और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त पर चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। विचारण न्यायालय ने पीडित चश्मदीद साक्षीगण पी. डब्ल्यू. 6 और 7 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 302, 458 और 324 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उसे मौत और क्रमशः 4 साल व 6 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की। इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं था क्योंकि चश्मदीद गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे करीबी रिश्तेदार थे और परिणामस्वरूप पक्षपाती गवाह थे और घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी; और कि वास्तविक हमलावर मृतक भाई और पीडब्लू 6 के दुश्मन हो सकते हैं; और मौत की सजा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामला "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" की श्रेणी में नहीं आता था; और आईपीसी की धारा 458 के तहत दोषसिद्धि अनुचित थी क्योंकि अपराध के तत्वों की उपस्थिति पर नीचे की अदालतों द्वारा चर्चा नहीं की

गई थी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया:-

1.1. संबंध किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। यदि गलत निहितार्थ का अनुरोध किया जाता है तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार होने के नाते एक पक्षपाती गवाह है और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। [383-सी; एच]

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. और. (1953) ऐसे. सी. 364; गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. और. (1974) ऐसे. सी. 276; वादिवेलु थेवर लेह्ला बनाम वी. मद्रास राज्य, ए. आई. और. (1957) ऐसे. सी. 614; मसाला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी (1965) ऐसेसी 202 और पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह बलजीत सिंह और करम सिंह, ए. आई. और. (1973) ऐसे. सी. 2407 का उल्लेख किया गया है।

1.2. घटना स्थल पर पीडब्लू 6 और 7 की उपस्थिति स्वाभाविक है। वे घर के निवासी थे, और इसलिए उनकी उपस्थिति के बारे में अभियुक्त द्वारा सुझाए गए किसी भी संदेह पर विचार नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि अभियुक्त और पीडब्लू 6 और 7 के बीच कुछ शत्रुता थी, यह अविश्वसनीय है कि वे वास्तविक दोषियों को गलत तरीके से फंसाने से बचाएँगे। तीखी प्रतिपरीक्षा के बावजूद उनकी गवाही खंडित नहीं हुई है। इसके विपरीत अभियुक्त पर किये गये हमले की स्वीकृति के तथ्य के संबंध में विश्वसनीयता बढी है। यह दलील कि मृतक भाई और पीडब्लू 6 की संदिग्ध साख के कारण उनके कई दुश्मन थे, और वे वास्तविक हमलावर हो सकते हैं, स्वीकार करने के लिए बहुत कम है। [384-जी-एच]

1.3. यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति पर चोट स्वयं प्रभावित नहीं करती है। अभियोजन संस्करण यदि विश्वसनीय है; जब समझाया नहीं गया है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार साक्ष्य की विश्वसनीयता को देखते हुए धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। [391-ई-एफ]

2. घायल गवाहों के पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 के निर्विवाद साक्ष्य को देखते हुए आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [385-सी]

3. चूँकि निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया

गया है कि कैसे धारा 458 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के तत्व मौजूद हैं, उक्त अपराध के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है। [385- सी]

4.1. मामले की असामान्य पृष्ठभूमि में, मौत की सजा उचित नहीं है। आजीवन कारावास की सजा ज्यादा उचित है। वाक्य को तदनुसार संशोधित किया जाता है। आरोपी की मानसिक स्थिति, जिसके कारण हमला हुआ, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे ही दोषसिद्धि का न्याय करने के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है। लेकिन दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय यह निश्चित रूप से एक कारक है। अपराध करने के लिए किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं है, हालांकि यह कृत्य क्रूर था, आरोपी जमीन हडप कर उसकी आजीविका से वंचित करके जैसा-कि सबूत से पता चलता है, अपनी नाराजगी और रोष का प्रदर्शन कर रहा था। झगड़ों की आवृत्ति लोगों की जान लेने के लिए किसी भी भयावह योजना की कमी का संकेत देती है। तथ्यात्मक परिदृश्य आवेगपूर्ण कार्य की छाप देता है न कि नियोजित हमलों की। [392-ए; 391-जी-एच]

4.2. दण्ड प्रक्रिया संहिता में आजीवन कारावास की ओर एक निश्चित स्विंग है। मौत की सजा को सामान्यतया निरसित कर दिया गया है और केवल 'विशेष' कारण पर ही जैसा कि धारा 354 (3) में दिया गया है, किया जा सकता है। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361 द्वारा विचार किए

गए 'विशेष कारण' ऐसे होने चाहिए जो न्यायालय को अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद यह अभिनिर्धारित करने के लिये मजबूर करें कि धारा 360 में सुधार और पुर्नवास करना असंभव है। धारा 361 और धारा 354 (3) दोनों ने एक ही समय में क़ानून की पुस्तक में प्रवेश किया है और वे अपराध विज्ञान में विधायिका द्वारा स्वीकृति की गई नये रूझानों की उभरती हुई तस्वीर का एक हिस्सा है। इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों से प्रकट होता है और अपराधी की सुधार के लिए व्यवहार्यता अनिवार्य रूप से दी जाने वाली सजा को निर्धारित करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा। [385- एफ-एच]

4.3. 1955 के अधिनियम XXVI द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 367(5) में संशोधन के बाद सामान्य हत्या के लिए दंड अब प्रभावी नहीं है और अब इस धारा में निर्धारित दो दण्डादेशों में से किसी एक को पारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर है; लेकिन दो दण्डादेशों में से जो भी वह पारित करता है, न्यायाधीश को एक विशेष दंड देने के लिए अपने कारण देने चाहिए। पुरानी संहिता की धारा 367(5) का संशोधन आई. पी. सी. के तहत सजा को विनियमित करने वाले कानून को प्रभावित नहीं करता है। यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और अब

न्यायालयों को मृत्युदंड नहीं देने के कारणों को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन वे कम सजा को प्राथमिकता देते हुए ठोस न्यायिक विचारों से अलग नहीं हो सकते हैं। [386- डी-एफ]

4.4. अपराध और सजा के बीच अनुपात का सिद्धांत- न्यायपूर्ण रेगिस्तान का सिद्धांत है जो प्रत्येक आपराधिक सजा की नींव के रूप में कार्य करता है जो न्यायसंगत है। आपराधिक न्याय के सिद्धांत के रूप में यह इस सिद्धांत से शायद ही कम परिचित या कम महत्वपूर्ण है कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह आवश्यक है कि सजा असमान रूप से बढी नहीं हो, जो न्यायपूर्ण रेगिस्तान का एक परिणाम है, उसी सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जाता है जो निर्दोष को दंड की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपराधिक आचरण के लिए जो योग्य दंड है उससे अधिक कोई भी दंड बिना दोष के सजा है। [390-ई-एफ।

4.5. सजा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में दण्ड का निर्धारण काफी हद तक अन्य विचारों द्वारा किया जाता है। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो दण्ड को सही ठहराने के लिए पेश की जाती हैं कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी-कभी यातायात भी उसके अपराध का परिणाम होता है। अनिवार्य रूप से ये विचार आधार के रूप में केवल रेगिस्तान न्याय से प्रस्थान का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के

मामले जो गंभीर और व्यापक हैं, पैदा करते हैं। संयुक्त रूप से असमान दंड के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं। [390- एच; 391-सी]

एडिगा अनाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एऔईऔर (1974) ऐसेसी 799; बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. और. (1980) ऐसे. सी. 898 और माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, [1983] 3 ऐसे. सी. सी. 470, संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या-733/2001

हत्या के संदर्भ सं. 7/2000 और सी. और. एल. सं. 659-डी. बी.2000 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.03.2001

विशाल मलिक (ए. सी.)-अपीलार्थी की और से।

जे.पी.दंडा और के.पी.सिंह-प्रतिपक्षी की और से।

अरिजीत पसायत, जे. लेहना (इसके बाद अभियुक्त के रूप में संदर्भित) को सोनीपत के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा "मौत की सजा" दी गई जिसकी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। उसके खिलाफ आरोप थे कि उसने अपनी मां, भाई और साली की जान ले ली। यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने अपने पिता सूरज मल

(पीडब्लू-6) और भतीजे चंद (पीडब्लू-7) को चोट पहुंचाई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धाराओं 302, 458 और 324 के तहत कथित रूप से दंडनीय अपराध करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें दोषी ठहराया गया और क्रमशः 4 साल और 6 महीने की सजा से दंडित किया गया और सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

अनावश्यक विवरण के बिना अभियोजन संस्करण इस प्रकार हैः

सूरज मल (पीडब्लू-6) के दो बेटे अर्थात आरोपी और जय भगवान (इसके बाद मृतक को उस नाम से संदर्भित किया गया) और एक छोटे भाई दरिया सिंह था। आरोपी और मृतक-जय भगवान अलग-अलग रह रहे थे। सूरज मल (पीडब्लू-6) के पास 10 एकड़ जमीन थी और उसने आरोपी को खेती के लिए 2 एकड़ जमीन दी थी। लेकिन आरोपी जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति और एक शराबी था, उसने बेकार के कामों में समय बर्बाद किया और खेती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस भूमि को अलग करने की कोशिश की जो उन्हें उनके पिता ने दी थी। इसके कारण सूरज मल (पीडब्लू-6) ने पुनर्विचार किया और जमीन को वापस ले लिया। इससे परिवार के सदस्यों के बीच गंभीर विवाद हो गया और वहाँ अक्सर झगड़ा होता था। 5 अगस्त 1998 को उनकी पत्नी सरोज घर की छत पर सो रहे थे। सूरज मल (पीडब्लू-6), उनकी पत्नी मनभरी, उनके पोते चंद (पीडब्लू-

7) और वजीर आंगन में सो रहे थे। आधी रात के बाद सूरज मल (पीडब्लू-6) ने घर की छत से एक आवाज़ सुनी और उसने बिजली की बत्ती चालू कर दी। चांद, वजीर और मनभरी जाग गए और वे ऊपर की ओर दौड़े और आरोपी गंडसे से लैस होकर मृतक सरोज व जय भगवान दोनों पर वार कर रहा था। इन दोनों को चोटें पहुँचाने के बाद, आरोपी सूरज मल (पीडब्लू-6) व अन्य की ओर मुड़ा, लेकिन वे डर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग गए। अभियुक्तों ने पीछा किया उन्हें और मनभरी को जमीन पर धकेलने के बाद उसकी गर्दन पर वार किए और जब पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन दोनों को भी पीटा। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पीडब्लू-6 ने पाया कि उसकी पत्नी पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उनके बेटे और बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगली सुबह, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा 302/458/324 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जो घायल चश्मदीद गवाह थे और अभियुक्त को अपराधों के लिए दोषी पाया। सजा के सवाल पर सुनवाई के बाद, उन्होंने ऊपर बताए अनुसार मौत की सजा सुनाई। यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 के संदर्भ में मौत की सजा की पुष्टि के लिए पंजाब और

हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, संदर्भ को स्वीकार कर लिया गया और अभियुक्त की दोषसिद्धि एवं कारावास के विरूद्ध दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष अपील के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि जिस साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष टिका था, उसका संस्करण रिश्तेदारों का था। एक ही संदिग्ध को प्रस्तुत करते हुए, शत्रुता स्वीकार की गई थी। अभियुक्त पर गंभीर प्रकृति की चोटों के बारे में नहीं बताया गया। इससे अभियोजन पक्ष की कमजोरी बढ गई। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि यह ऐसा मामला नहीं है जो मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी से संबंधित हो। विद्वान वकील के अनुसार विवेक का उपयोग न करना इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 458 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए उसके अपने घर में अतिक्रमणकारी माना गया है। इस बात पर चर्चा नहीं है कि उस धारा की सामग्री कैसे मौजूद है।

जवाब में, हरियाणा राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि वहाँ रिश्तेदारों की साक्ष्य पर दोषसिद्धि पर कोई परिवीक्षा संभव नहीं है। इसके

अतिरिक्त, अभियुक्त पर चोटों, यदि कोई हो, का केवल गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष के संस्करण पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। हमलों की क्रूर प्रकृति, जिसके परिणामस्वरूप तीन मूल्यवान लोगों की जान चली गई, पोस्टमॉर्टम में देखी गई चोटों की प्रकृति और घायल गवाहों की जांच से स्पष्ट है। संक्षेप में, प्रस्तुतिकरण इस आशय का था कि इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हम पहले अभियोजन पक्ष के संस्करण को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रूचि से संबंधित विवाद पर विचार करेंगे। संबंध गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। यदि गलत फसाने की दलील दी गई तो इसे आधार बनाना होगा। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. और. (1953) ऐसे. सी. 364 इसमें निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

> " एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि गवाह के पास कारण न हो, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ शत्रुता, उसे गलत तरीके से फंसाना

चाहते हैं। आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जाँच करने और निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सच है, जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और दुश्मिनी का व्यक्तिगत कारण हो तो वहां निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक गवाह की दोषी के साथ दुर्भावना है, लेकिन इस तरह की आलोचना और केवल तथ्य के लिए नींव रखी जानी चाहिए। एक नींव से दूर अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी है। हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणी को केवल विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने आने वाले मामलों में मुकाबला करने के लिये बनाया गया है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले में इसे अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्णय के बाद से गुली चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. और. (1974) ऐसे. सी. 276 में इसका पालन किया गया है, जिसमें वादिवेलु थेवर

बनाम. मद्रास राज्य, ए. आई. और. (1957) ऐसे. सी. 614 पर भी भरोसा किया गया था।

हम यह भी देख सकते हैं कि इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप एक पक्षपाती गवाह होने पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इस दलील में कोई दम नहीं है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने दलीप में पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था और जो बार के सदस्यों के मन में प्रचलित था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। जे. विवियन बोस के माध्यम से बोलते हुए, यह देखा गयाः

" हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता है। अगर इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएँ हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनकी गवाही पर टीका हुआ है, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह कारण पर आधारित है कि वे मृतक से निकट संबंध रखते हैं, हम सहमत होने में असमर्थ हैं।यह कई आपराधिक मामलों में एक आम भ्रांति है और जो इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस मामले को खारिज करने का प्रयास किया-रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य', ए. आई. और.

(1952) ऐसे. सी. 54 पी. 59 (ए)में हम पाते हैं, हालाँकि यह न्यायालय के निर्णयों में नहीं बल्कि किसी भी दर से वकीलों की दलीलों में अभी भी बना हुआ है।

इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"लेकिन हम सोचते हैं कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि- गवाहों द्वारा दिए गए बयान को केवल इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि पक्षपाती या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य है। इस तरह के साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिकी अस्वीकृति देना कि वह पक्षपातपूर्ण है, हमेशा न्याय की विफलता की ओर ले जाता है। इस तरह का कोई कठोर और शख्त नियम नहीं है कि कितने सबूतों की सराहना की जानी चाहिये। न्यायिक दृष्टिकोण को ऐसे साक्ष्य से निपटने में सावधान रहना होगा; लेकिन यह दलील कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, बलजीत सिंह और करम सिंह, एऔईऔर (1973) ऐसेसी 2407 में भी इसी प्रभाव का निर्णय लिया गया है।

घटना स्थल पर पीडब्लू 6 और 7 की उपस्थिति स्वाभाविक

है। वे घर के निवासी थे और इसलिए उनकी उपस्थिति के बारे में अभियुक्त द्वारा सुझाए गए किसी भी संदेह पर विचार नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि अभियुक्त और पीडब्लू 6 और 7 के बीच कुछ शत्रुता थी, यह अविश्वसनीय है कि वे अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक दोषियों को बचा लेंगे। तीखी प्रतिपरीक्षा के बावजूद उनकी गवाही खंडित नहीं हुई। इसके विपरीत अभियुक्त पर हमले के तथ्यों के संबंध में उनकी स्वीकृति के कारण इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। यह दलील कि मृतक जय भगवान और सूरज मल (पीडब्लू-6) की संदिग्ध साख के कारण उनके कई दुश्मन थे, और वे असली हमलावर हो सकते हैं। यह वारण्ट स्वीकार करने के लिये बहुत कम है।

जैसा कि- उपर विश्लेषण की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये हुये इस दलील में कोई दम नहीं है कि पी.डब्ल्यू-6 व पीडब्ल्यू-7 की साक्ष्य केवल इस कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि वह मृत व्यक्ति के रिश्तेदार थे।

जैसा कि अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं किया गया है कि कैसे -आई. पी. सी. की धारा 458 के तहत दंडनीय अपराध की सामग्री मौजूद है। यह स्थिति होने के कारण, उक्त अपराध के लिए दोषसिद्धि को खारिज किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप सजा

दी जाती है। पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के घायल गवाहों की निर्विवाद साक्ष्य को देखते हुए, आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण महत्व का दूसरा सवाल यह है कि क्या मौत की सजा उचित है। आई. पी. सी. की धारा 302 में हत्या के लिये मृत्यु या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ऐसा करते समय, संहिता न्यायालय को उसके आवेदन के बारे में निर्देश देती है। पिछले तीन दशकों में संहिता में जो बदलाव हुए हैं, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि संसद समकालीन आपराधिक विचारधारा और गतिविधि पर ध्यान दे रही है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि संहिता में आजीवन कारावास की ओर एक निश्चित रुख है। मौत की सजा को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है और केवल 'विशेष कारणों' के लिए लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354 (3) में दिया गया है। संहिता में एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति 'विशेष कारण' का भी उपयोग करता है। यह धारा 361 है। 1973 की संहिता की धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (संक्षेप में 'पुरानी संहिता') की धारा 562 को सारतः फिर से अधिनियमित करती है। धारा 361, जो संहिता में एक नया प्रावधान है, न्यायालय के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए 'विशेष कारणों' को दर्ज करना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य

डालती है कि वह जहां तक संभव हो, धारा 360 के प्रावधानों को लागू करें और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो विशेष कारण बताए। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361 द्वारा विचार किए गए 'विशेष कारण' ऐसे होने चाहिए जो न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर करें कि अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और उसका पुनर्वास करना असंभव है जिनमें अपराध किया गया था। यह विधानमंडल द्वारा कुछ संकेत है कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, न कि केवल प्रतिरोध हो, अब हमारे देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। यह धारा 361 और धारा 354(3)दोनों ने एक ही समय में संविधि पुस्तक में प्रवेश किया है और वे अपराध विज्ञान में नये रूझानों की विधायिका द्वारा स्वीकृति की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं। अतः यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व उसकी आयु चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियाँ से प्रकट होता है और व्यवहार्यता सुधार के लिए अपराधी को अनिवार्य रूप से सबसे प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए दिए जाने वाले दंड का निर्धारण करना। विशेष कारणों का इन कारकों से कुछ संबंध होना चाहिए। आपराधिक न्याय जटिल मानवीय समस्याओं और विविध मानवों से संबंधित है। एक न्यायाधीश को तथ्यों,परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ अपराधी के व्यक्तित्व को संतुलित करना होता है और उचित सजा का चयन करना होता है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (XXVI) द्वारा पुरानी संहिता की धारा 367 (5) का संशोधन औईपीसी के तहत सजा के कानून को प्रभावित नहीं करता है। यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और अब अदालतों को मृत्यु दंड की सजा नहीं दिये जाने के कारणों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे कम सजा को प्राथमिकता देते हुये ठोस न्यायिक कारणों से विमुख नहीं हो सकते।

संहिता की धारा 354 (3) 1 अप्रेल, 1974 से ठीक पहले लागू पुरानी संहिता में अंतर्निहित विधायी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके अनुसार हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दोनों की वैकल्पिक सजाएं सामान्य सजाएं थीं। अब, संहिता की धारा 354 (3) के तहत हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है और मृत्युदंड एक अपवाद है। अदालत को दी गई सजा के कारण बताने की आवश्यकता होती है और मौत की सजा के मामले में 'विशेष कारण' बताए जाने की आवश्यकता होती है, यानी केवल विशेष तथ्य और परिस्थितियाँ मौत की सजा को पारित करने की गारंटी देंगी। यह संहिता में इन क्रमिक विधायी परिवर्तनों के आलोक में है कि न्यायिक निर्णय 1955 के अधिनियम 26 और फिर 1974 के अधिनियम 2 द्वारा किए गए संशोधन से पहले समझने की जरूरत है।

एडिगा अनम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एऔईऔर (1974) ऐसेसी 799) ने कहा हैः"आइए हम मृत्यु के खिलाफ सकारात्मक संकेतकों को स्पष्ट करें वर्तमान में भारतीय कानून के तहत सजा। जहाँ हत्यारा बहुत छोटा या बहुत बूढा है, वहाँ दंडात्मक न्याय की दया उसकी मदद करती है। जहाँ अपराधी सामाजिक, औथिक,मानसिक दण्डात्मक आवश्यकता से ग्रसित है जो कानूनी अपवाद को आकर्षित करने या अपराध को कम करने के लिए अपर्याप्त है। न्यायिक आदान प्रदान किया जा सकता है। अन्य सामान्य सामाजिक दबाव, न्यायिक नोटिस की गारंटी देते हैं, जिसका प्रभाव कम होता है, विशेष मामलों में कम दण्ड दिया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में असाधारण विशेषताएं, जैसे कि मौत की सजा अपराधी के सिर पर अत्यधिक लंबे समय तक लटकी हुई है, अदालत को दयालु होने के लिए राजी कर सकती है। इसी तरह, यदि अन्य लोग अपराध में शामिल हैं और समान रूप से स्थित लोगों को आजीवन कारावास का लाभ प्राप्त हुआ है या यदि अपराध केवल धारा 302 के तहत रचनात्मक है,जो धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है, या फिर आरोपी ने बिना किसी मध्यस्थता के अचानक दूसरे के उकसावे के तहत काम किया है, तो शायद अदालत मानवीय रूप से जीवन का विकल्प चुन सकती है, जहाँ कि बेवफाई के न्यायसंगत कारण या संदेह ने अपराधी को अपराध में धकेल दिया हो। दूसरी ओर, उपयोग किए गए हथियार और उनके उपयोग का तरीका, अपराध की भयानक विशेषताएं और पीड़ित की असहाय, असहाय

स्थिति, और इसी तरह, एक कठोर सजा के लिए कानून का दिल मजबूत करते हैं। हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वे एक अपूर्ण और लहरदार समाज में ज्योतिषीय रूप से असंभव है। जीवन या मृत्यु पर एक कानूनी नीति को तदर्थ मनोदशा या व्यक्तिगत झुकाव के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए हम प्रतिशोधात्मक क्रूरता को त्यागते हुए, निवारक पंथ में संशोधन करते हुए और जीवन को बाहर निकालने के चरम और अपरिवर्तनीय दंड के खिलाफ प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए, यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. और. (1980) ऐसे. सी. 898, यह देखा गया कि "मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के साधन के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को दर्शाती है। ऐसा दुर्लभतम मामलों को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प को निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है। गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का उपयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रश्न और

जवाब दिये जा सकते हैंः-(ए) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा की मांग करता है और (ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो अपराधी के पक्ष में बोलते हैं। एक और निर्णय जो मृत्यु के प्रश्न से संबंधित है। वाक्य माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, [1983] 3 ऐसेसीसी 470।

माची सिंह और बचन सिंह के मामलों (ऊपर) में, दिशानिर्देश जिनका इस सवाल पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी से संबंधित है, जिसमें मौत की सजा दी जा सकती है।

" निम्नलिखित प्रश्न एक परीक्षण के रूप में पूछे और उत्तर दिए जा सकते हैं -

(क) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त करता है और मृत्यु की माँग करती है।

(ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देती है और मौत की सजा के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

बचन सिंह के मामले से निम्नलिखित दिशा-निर्देश सामने आए हैं (उपर्युक्त) प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू होना होगा जहां मृत्युदंड के अधिरोपण का प्रश्न उत्पन्न होता हैः

(i) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीर मामलों को छोडकर मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले,अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ "अपराधी' की परिस्थितियोंको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। मौत की सजा तभी दी जानी चाहिए जब उसे आजीवन कारावास अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों में पूरी तरह से अपर्याप्त सजा प्रतीत हो और यह प्रदान किया गया कि बशर्ते, अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने के विकल्प का ईमानदारी से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(iv) गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन-पत्र तैयार करने के लिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और पहले से ही बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा।

दुर्लभतम मामलों में जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा सदमे में

हैं, कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मृत्युदंड को बनाए रखने की उम्मीद करेगा। वांछनीयता के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड दिया जा सकता है। समिति निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना का मनोरंजन कर सकती हैः

(1) जब हत्या एक अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही, या कायरतापूर्ण तरीके से की जाती है ताकि गंभीर रूप से उत्तेजित किया जा सके और समुदाय अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।

(2) जब हत्या एक ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है; जैसे। पैसे या इनाम के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या; या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या, जिसे हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है; या मातृभूमि के साथ विश्वासघात के लिए हत्या की जाती है।

(3) जब किसी अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, बल्कि उन परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं, या 'दुल्हन को जलाने' या 'दहेज हत्या' के मामलों में या जब दहेज लेने के लिए फिर से शादी करने के लिए हत्या की जाती है या मोह के कारण किसी अन्य महिला से शादी करना।

(4) जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जब एक परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या एक विशेष जाति के बड़ी संख्या में व्यक्तियों की कई हत्याएं, समुदाय, या स्थान, प्रतिबद्ध हैं।

(5) जब हत्या का शिकार एक निर्दोष बच्चा हो, या असहाय हो महिला या वृद्ध या अशक्त व्यक्ति या एक व्यक्ति जिसके खिलाफ हत्यारा हावी स्थिति में है, या एक सार्वजनिक व्यक्ति जो आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में होता है। समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान किया जाता है।यदि सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए उपरोक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए और उनके उत्तरों को ध्यान में रखते हुए दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों के लिए परीक्षण के माध्यम से पूछे गए प्रश्न, मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युदंड की सजा दी जाती है, न्यायालय ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब अपराध की गंभीरता और पर्याप्त सजा के निर्णय पर विचार किया जाता है, तब एक दोषी जीवन और मृत्यु के बीच झूलता है। मानव जाति प्रकृति की स्थिति से एक सभ्य समाज की ओर स्थानांतरित हो गई है और यह अब बहुमत की भौतिक राय नहीं है जो किसी नागरिक को दोषी ठहराकर और उसे कारावास की सजा देकर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। कानून के शासन से जुड़ी प्रणाली में एक मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का पुरस्कार अदालत में शांत विचार-विमर्श का परिणाम है। पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई के बाद, अभियुक्त के

खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, अभियोजन पक्ष को अपनी बेगुनाही स्थापित करके आरोपों को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। सुविचारित विचार-विमर्श और जानकार व्यक्ति द्वारा सामग्री की जांच का परिणाम है जो विधि के निर्धारण की ओर ले जाती है।

अपराध और सजा के बीच अनुपात का सिद्धांत एक न्यायपूर्ण रेगिस्तान का सिद्धांत है, जो हर उचित आपराधिक सजा की नींव के रूप में कार्य करता है जो न्यायसंगत है। आपराधिक न्याय के सिद्धांत के रूप में यह इस सिद्धांत से शायद ही कम परिचित या कम महत्वपूर्ण है कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह आवश्यकता कि सजा असमान रूप से बड़ी न हो, जो कि न्यायपूर्ण रेगिस्तान का एक परिणाम है, उसी सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती है जो निर्दोष को सजा की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपराधिक आचरण के लिए जो भी सजा योग्य है, उससे अधिक कोई भी सजा अपराध के बिना सजा है।

आपराधिक कानून सामान्य रूप से प्रत्येक प्रकार के अपराधी की दोषसिद्धि के अनुसार दायित्व निर्धारण करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में एक सजा पर पहुंचने में कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है, संभवतः ऐसे मामलों की अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोष के अधिक सूक्ष्म विचारों को दर्शाते हैं। सजा

हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में सजाएं काफी हद तक अन्य विचारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो एक सजा को सही ठहराने के लिए पेश की जाती हैं; कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी-कभी उसके अपराध का शीघ्र परिणाम भी होती है। अनिवार्य रूप से ये विचार सजा के आधार के रूप में न्यायपूर्ण रेगिस्तान से प्रस्थान का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करते हैं। जो गंभीर और व्यापक हैं।

अपराध और समाज के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया जाता है, बावजूद यह सजाओ के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। सभी गंभीर अपराधों को समान गंभीरता के साथ दंडित करने की प्रथा अब सभ्य समाजों में अज्ञात है; लेकिन इस तरह के एक कट्टरपंथी आनुपातिकता के सिद्धांत से विचलन हाल के दिनों में ही कानून से गायब हो गया है। ऐसा माना जाता है कि अब भी एक गंभीर उल्लंघन के लिए समान रूप से कठोर उपायों की आवश्यकता है। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम गंभीर दंड से कम की सजा को सहिष्णुता का एक उपाय माना जाता है जो अनुचित और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में उन विचारों से काफी अलग है जो दंड को अनुचित बनाते हैं जब यह अपराध के अनुपात से बाहर होता है। संयुक्त रूप से

असंगत सजा के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक हैं।

जैसा कि पृष्ठभूमि के तथ्यों से पता चलता है कि आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भूमि का विवाद था। ऐसा लगता है कि आरोपी को उनके पिता द्वारा उनसे जमीन छीनने पर आपत्ति जताई है। जैसा कि सबूत से पता चलता है, वह अपने भाई, साली को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। यह भी सबूत है कि घटना से दो-तीन दिन पहले आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच गंभीर झगड़ा हुआ था। पीडब्लू-7 की साक्ष्य यह है कि हमेशा एक तरफ पीडब्लू-6 मृतक जय भगवान, मृतक सरोज और दूसरी तरफ आरोपीगण के बीच पैतृक भूमि को लेकर लगातार झगडा होता रहता था। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मृतक जय भगवान नैतिक चरित्र के नहीं थे और पीडब्लू-6 ने मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसके लिए ग्रामीणों ने उनके घर के एक हिस्से में आग लगा दी थी। यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति की चोटें विश्वसनीय होने पर अभियोजन पक्ष के बयान को प्रभावित नहीं करती हैं। जब समझाया नहीं जाता है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है यदि वे गंभीर प्रकृति के हैं। यह तथ्य विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त को चोटें लगी थीं। वास्तव में, पीडब्लू-7 ने स्वीकार किया है कि पीडब्लू-6 ने तीन अभियुक्त व्यक्तियों पर हमलों के बाद अदालत के प्रांगण में अभियुक्त को पूरी तरह से पीटा था। जैसा कि चिकित्सीय साक्ष्य से पता

चलता है, अभियुक्तों को लगी चोटें बहुत गंभीर प्रकृति की थीं। यह सच है कि तीन लोगों की जान चली गई है। लेकिन साथ ही, आरोपी की मानसिक स्थिति, जिसके कारण हमला हुआ, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह बात दोषसिद्धि का न्याय करने के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है। लेकिन सजा के प्रश्न पर विचार करते समय यह निश्चित रूप से एक कारक है। अपराध करने के लिए किसी भी शैतानी योजना का कोई सबूत नहीं है, हालांकि यह कृत्य क्रूर था। आरोपी जमीन छीनने के कारण अपनी आजीविका से वंचित होकर, जैसा कि सबूत से पता चलता है, नाराजगी का प्रदर्शन कर रहा था। लगातार झगडे मृतक का जीवन छीनने की भयावह योजना की कमी का संकेत देते हैं। तथ्यात्मक परिदृश्य आवेगपूर्ण कार्य की छाप है न कि नियोजित हमलों का। अजीबोगरीब पृष्ठभूमि में मौत की सजा उचित नहीं होगी, आजीवन कारावास की सजा अधिक उपयुक्त होगी। तदनुसार सजा को संशोधित किया जाता है, जबकि धारा 302 औई.पी.सी.के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

उपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। हम भी विशाल मलिक द्वारा प्रदान की गई सहायता की प्रशंसा करते हैं, जिन्हें न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

अपील स्वीकार

नोटः- यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सावित्री सिंह (और.जे.ऐसे.)द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए,निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।